46. MAHI HIGH
47. DAHEJ
48. LOHAR
49. LANGHANA
50. KUDARA
51. MEWAD
52. CGNAJ
53. MODHERA
54. GAMIJ
55. SANGANPUR
56. WADU-PALIYAD
57. SOUTH MEWAD
58. DHOLASAN (SOUTH)
59. SOUTH VIRAJ
60. GANDHAR
61. LIMBODRA
62. NARJISAN
63. PAKHAJAN
64. S. MALPUR
65. BECHARAJI
66. ELAD
67. WEST UNAWA
68. MOTERA
69. NADA
70. MANSA
71. WEST BECHARAJI
72. ANDADA
73. S.W. PATAM
74. PALEJ
75. NANDEJ
76. KIM
77. KHAMBEL
78. HALISA*

* UNDER ASSESSMENT

ग्वालियर में भंडेर में गैस आधारित विद्युत परियोजना

6765. **श्री अजीत जोगी:** क्या **पट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में भंडेर में हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर गैस पाइपलाइन के निकट एक गैस आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने मध्य प्रदेश की उक्त परियोजना के लिये गैस आवंटन के बारे में क्या निर्णय लिया है; और

(घ) क्या सरकार मध्य प्रदेश के विशाल क्षेत्रफल, आदिवासी बाहुल्य जनसंख्या समग्र रूप से पिछड़ापन और हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर पाइपलाइन का सबसे बडा हिस्सा इस प्रदेश से होकर गुजरने आदि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश को अतिरिक्त गैस आवंटन करने पर विचार करेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) से (घ) भंडेर, ग्वालियर में गैस आधारित विद्युत संयंत्र के लिए प्राकृतिक गैस के आबंटन हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं। चूंकि एच बी जे पाइपलाइन से उपलब्ध होने वाली अनुमानित गैस पूर्णतः आबंटित कर दी गई है अतः इस परियोजना के लिए आबंटन करना व्यवहार्य नहीं है।

Privatisation of Oil Fields in Assam

6766. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the major opposition parties, both national and regional, in Assam were opposed to the proposed privatisation of oil fields in Assam; and

(b) if so, what steps are being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA): (a) and (b) Doubts had been expressed in certain quarters about the involvement of private parties for purposes of exploration and development of oil fields. The rationale for the Government policy for inviting private participation has been explained to the concerned groups.